

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—स्वरह 3—उपखण्ड (li)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326]

मद विरुली, शक्तवार, जुलाई 22, 1977/बाबाइ 31, 1899

No. 326]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 1977/ASADHA 31, 1899

इस भाग में भिन्न पष्ट संख्या की जाती हैं जिससे कि यह असग संकलम के रूप में रखा का सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July 1977

- S.O. 580(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Finance Commission (Miscellaneous Provision) Act, 1951 (33 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission (Salaries and Allowances) Rules, 1951, namely:—
- 1. These rules may be called the Finance Commission (Salaries and Allowances) Amendment Rules, 1977
- 2. In rule 2 of the Finance Commission (Salaries and Allowances) Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for the words "Provided that where any person so appointed", the following shall be substituted, namely —

"Provided that where any person who had been a Judge of the Supreme Court is appointed as the Chairman of the Commission, he shall be entitled—

(i) to a monthly salary at the same rate as was admissible to him as a Judge of the Supreme Court immediately before relinquishing office as such Judge, reduced by pension and pension equivalent of other forms of retirement benefits drawn by him:

- (11) (a) in respect of journeys undertaken for assuming charge as Chairman of the Commission, to the actual railway fare not exceeding the fare for the highest class including the air-conditioned class, for self and members of the family from the ordinary place of his residence to New Delhi, plus, the actual cost on transport, by passenger train, at owner's risk, of one motor car plus actual cost on transport of other personal effects not exceeding the expenditure which would be incurred on the transport of a full wagon of goods and the expenditure incurred on loading and unloading of such personal effects,
 - (b) in respect of travelling on duty as Chairman of the Commission, to the allowances as are admissible to a Judge of the Supreme Court in accordance with rule 5, excluding item (i) of the third proviso to clause (f) thereof, of the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, as in force for the time being; and
 - (c) on relinquishing charge as Chairman of the Commission, to the facilities as are admissible to a Judge of the Supreme Court on retirement from service, in accordance with sub-rule (3) of rule 6 of the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, as in force for the time being, and
- (111) to the use of a fully furnished residence in New Delhi throughout his term of office and for a further period of 15 days immediately thereafter, without payment of any rent for such use.

Provided further that where any person, other than a person who had been a Judge of the Supreme Court, so appointed".

- 3. In rule 3 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely .---
 - , '(3) A person, being a retired Government servant or a retired servant of the Reserve Bank (other than a retired High Court Judge) appointed to render whole-time service as a Member of the Commission shall be entitled—
 - (a) to a monthly salary at the same rate as was admissible to him immediately before retirement from service of the Government or, as the case may be, from service of the Reserve Bank, reduced by pension and pension equivalent of other forms of retirement benefits drawn by him;
 - (b) to draw travelling allowance, including daily allowance, for any journey performed by him as a Member of the Commission at such rates as are admissible to a Government servant of the First Grade;
 - (c) to draw compensatory allowance at the rate of Rs. 75 per mensem, and
 - (d) when not in occapition of a residence provided by the Central Government, to house rent allowance at the same rate and subject to such terms and conditions as are applicable, from time to time, to a serving Government servant of equivalent status".

[No. 13(1)-B(S)/77]

K N. ROW, Jt. Secy.

विहा मत्रालय

(म्राधिक कार्य विभाग)

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1977

का० ग्रा० 580(ग्र).—-केन्द्रीय सरकार, वित्त श्रायोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) श्रधिनियम, 1951 (1951का 33) की धारा 7 द्वाराप्रदत्त णक्तियो का प्रयोग करते हुए, वित्त श्रायोग्। (वेतन श्रौर भत्ता) नियम, 1951 में श्रौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, श्रयित्.—

1 इन नियमो का नाम वित्त आयोग (वेतन और भत्ता) संशोधन नियम, 1977 है।

2 वित्त ग्रायोग (वेतन ग्रीर भत्ता) नियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, उप-नियम (1) में "परन्तु यह कि वहा जहां इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति" णब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, ग्रर्थात् :---

"परन्तु यह कि जहा कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का यायाधीश रह चुका है, भ्रायोग का भ्रध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वहां वह निम्नलिखित का हकदार होगा—

- (i) उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मे ग्रपना पदभार छोड़ने के ठीक पूर्व ऐसे न्यायाधीश के रूप मे उसे अनुज्ञेय दर पर मासिक वेतन, उसमे से उसके द्वारा ली गई पेंशन श्रीर ग्रन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदो के समतुल्य पेशन कम करने के पश्चात् ,
- (ii) (क) आयोग के श्रध्यक्ष के रूप मे पदभार, ग्रहण करने के लिए की गई याद्राश्चों की बाबत, अपने सामान्य निवास स्थान से नई दिल्ली तक श्रपने लिए तथा श्रपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए वास्तविक रेल भाडा जो, वातानुकृतित श्रेणी महित, उच्चत्तम श्रेणी के भाडे से श्रिधिक नहीं होगा और इसके श्रितिर्दिक्त याद्री गाडी से, स्वामी के जोखिम पर, एक मोटर कार के परिवहन का वास्तविक खर्च और अन्य व्यक्तिगत माल-श्रसबाब के परिवहन का वास्तविक खर्च, जो मालगाडी के पूरे दिव्हों के परिवहन पर उपगत खर्च से अधिक नहीं होगा तथा ऐसे व्यक्तिगत माल-श्रसबाब को लादने और उतारने पर उपगत खर्च,
 - (ख) द्यायोग के द्यव्यक्ष की हैिमियत से कर्तव्य पर यात्रा की बाबत, तत्समय यथाप्रवृत्त उच्चत्तम त्यायालय न्यायाधीण (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 के नियम 5 के प्रनुमार, खण्ड (च) के तीसरे परन्तुक की मद सं० (i) को छोड कर, उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीण को प्रनुज्ञेय के प्रनुसार भक्ते; ग्रीर
 - (ग) म्रायोग के म्रध्यक्ष का पद त्यागने पर, तत्समय यथाप्रवृत्त उच्चत्तम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 के नियम 6 के उपनियम (3) के म्रनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सेवा से निवृत्त होने पर, म्रनुशेय के म्रनुसार सुर्विधाए; तथा
- (iii) उसके पूरे कार्यकाल के दौरान भीर उसके तुरन्त पश्चात् 15 दिन की भीर अवधि तक नई दिल्ली में पूर्णत सुसज्जित वगैर भाडे के वास-सुविधा

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो उस व्यक्ति से भिन्न है जो उच्चत्तम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है ''।

- 3. उक्त नियमो के नियम 3 मे, उप-नियम (3) के स्थान पर, निग्नलिखित उप-निययम रखा जाएगा, भ्रर्थात् ---
 - "(3) वह व्यक्ति जो ग्रायोग को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ग्रौर जो सेवा निवृत्त सरकारी सेवक या रिजर्व बेंक

मेवा निवृत्त सेवक (उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश से भिन्न) है तो वह निम्नलिखित का हकदार होगा –

- (क) यथास्थिति, सरकार की सेवा से या रिजर्थ बैंक की सेवा से निवृत्त होने के ठीक पूर्व उसे भ्रतुकोय दर पर मासिक बेनन ,उसमें से उसके द्वारा ली गई पेंशन और भ्रत्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन कम करने के पश्चात् ,
- (ख) भ्रायोग के सदस्य के रूप में उसके द्वारा की गई किसी याता के लिए उन दरो से यात्रा भत्ता, जिसमें दैनिक भत्ता भी जाता है, जो प्रथम श्रेणी से सरकारी सेवक की अनुक्रेय है ,
- (ग) 75 रुपए प्रति मास की दर से प्रतिकरात्मक भत्ता ; श्रौर
- (घ) यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए भ्रावास मे नहीं रह रहा है तो उसी दर से श्रीर उन्हीं निबन्धनों श्रीर शर्ती के भ्रावीन गृहभाटक भत्ता जो समतुल्य परिस्थिति के नेवारत सरकारी सेवकों को समय समय पर श्रनुक्रेय हैं "।

[सं॰ 13(1)-बी(एस)/77]

के० एन० राव, संयुक्त सचिव ।

ERRATA

In the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No S.O. 761(E) dated 1st December, 1976 published in Part II, Section 3, Subsection (ii) of the Gazette of India Extraordinary, appearing on pages 2147 to 2154, on page 2148, in Para 3 in line 8 the words and figure "1st January, 1976" may be read as "1st January, 1978".